

बिहार में बंपर भर्ती, 2000 से ज्यादा
शिक्षा सेवकों की होगी नियुक्ति, एसीएस
एस सिद्धार्थ ने जारी किया आदेश

पटना, एजेंसी। बिहार के विभिन्न जिलों में 2206 रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों (तालीमी मकान) की नियुक्ति होगी। इसकी चयन प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसके लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि महादलित, बहिन, अलसांख्यक अतिपिछड़ा वर्ग और अंतर्वर्तीयों को तहत जिलों में शिक्षा सेवक कार्यकरत हैं। रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जून, 2024 में ही रिसाइड दिया गया था।

इसके बाद भी अब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि जहाँ सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, वहाँ 15 जून तक शिक्षक सेवकों को चयन कर ले। बहिन, जहाँ सर्वेक्षण का काम अधूरा है, वहाँ पर 30 जून तक चयन प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।

समस्तीपुर से रद्द ट्रेनों का परिचालन शुरू : कई ट्रेन के रूट में हुआ बदलाव

समस्तीपुर, एजेंसी। समस्तीपुर रेलवे प्रशासन की तरफ से कैसर्पी-गोरखपुर कैट-गोरखपुर ज.- डोमिनांड-तीसरी लाइन निर्माण को गोरखपुर ज.- गोरखपुर-कैट के मध्य तीसरी लाइन के प्रावधान और गोरखपुर ज.-स्टेशन की यार्ड-रिमॉडलिंग के परिप्रेक्ष में रद्द की गई ट्रेनों का प्रचलन 16 अप्रैल से फिर से शुरू किया जा रहा है।



दरभंगा से 16 अप्रैल से खुलने वाली 15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-छावा ग्रामीण- वाराणसी-सुलतानपुर-लखनऊ- रोजा के रास्ते चलाई जायेगी।

अमृतसर से 18 अप्रैल खुलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रोजा-लखनऊ-सुलतानपुर- वाराणसी-छावा ग्रामीण- मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी।

रखसौल से 16 अप्रैल से 03 मई, 2025 तक खुलने वाली 15273 रखसौल-अनन्द बिहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सागरी-मुजफ्फरपुर-छावा ग्रामीण-वाराणसी-सुलतानपुर- लखनऊ-रोजा के रास्ते चलाई जायेगी।

आनन्द बिहार टर्मिनस से 15 अप्रैल से 04 मई तक खुलने वाली 15274 अनन्द बिहार टर्मिनस-रखसौल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सागरी-मुजफ्फरपुर-छावा ग्रामीण-वाराणसी-सुलतानपुर- लखनऊ-रोजा के रास्ते चलाई जायेगी।

राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर राजपूत समाज ने जताया आक्रोश

बक्सर, एजेंसी। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर जिला राजपूत समाज ने मगलवार को शहर के गोलंदार से आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च यमुना चौक, सल्टवेंडवांग होते हुए बीर कुंवर सिंह चौक पर पहुंच संपन्न हुआ। राजपूत समाज के लोगों ने उनकी आत्मकद प्रतीमा पर मालयापी किया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व जोगेंद्र सिंह एवं संचालन कृष्ण सिंह ने किया कि संसद के उच्च सदन राजसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने हिन्दू समाज के आदर्श वीर शिरोमणि राणा सांगा पर अमर्यादित बयान देते हुए उनको



गहर एवं उनके वंशजों को गद्दर कहा है। आक्रोश मार्च के माध्यम से राजपूत समाज ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्त्रपति को सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राज्य सभा की सदस्यता समाज करने वे किसी भी मात्रा में हथियार और हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किया गया। पुलिस छपेमारी से पहुंच ही आरोपी फरार हो गया। बताया कि इसके बारे में शास्त्रीय रूप से चुक्री हो चुकी है।

छपेमारी के दौरान अवैध हथियार बरामद- पुलिस ने छपेमारी के दौरान एक निर्मित देसी पिस्टल, चार नियोनी, चार मैगजीन, तीन डिल मशीन और हथियार बरामद किया है। इसमें प्रयुक्त होने वाली भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह अवैध मिरी गन फैट्री लेवे समय से इनका में सक्रिय थी। यहाँ स्थानीय और बाहरी लोग लगातार हथियारों के निर्माण और सलाह के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पुलिस को गुप्त सूत्रों मिली थी कि घोरवट इलाके में हथियारों का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके बाद घापेमारी की गई। थाना प्रभारी विवक जायसवाल ने बताया कि इसके पांच और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से गहराई से पूछाता की जा रही है ताकि इस अवैध धंधे के पूरे नेटवर्क का पार्दाकाश किया जा सके।

बिहार के 22 जिलों में बारिश-आंधी का यात्रा अलट: 19 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम

पटना, एजेंसी। बिहार में मिलाहाल मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग के द्वारा 22 जिलों के लिए यह अलट जारी किया है। इन जिलों में हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की अशक्ति है। इस दौरान इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, मौसम में आए बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में शिरावट आई है। अने वाले 4-5 दिनों तक अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की स्थिति है। वर्षीय छपेमारी 48 घंटे में जुहू में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। यहाँ 48.6 एम्पर बारिश रिकॉर्ड किया गया। बिहार आंधिक संवर्क्षण के अनुसार 2022-23 में राज्य में बिजली और आधी-तूफान से 400 घोंड़ हुए। इस साल तक बारिश दर्ज की गई है। हाल के वर्षों से बिहार के साथ आकाशीय बिजली और आंधी चुनौती बनी है।

इसके अलावा जुहू, बांका, मुंगे, भगलपुर, खांडिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, बैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सीवान, गापालगंज, पूर्णी और पश्चिमी चंपारण में शामिल हैं। भारत मौसम विभाग (आईएम्सी) ने भी माना है कि बिहार, ठाना के साथीकृत बारिश को लेकर अलट है।

प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना- बिहार में पुरावा हवा चल रही है, जो बगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही है। इसका असर प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है, जिससे मौसम में बदलाव दिख रहा है। 19 अप्रैल तक आंधी-बारिश को लेकर अंरेंज अलट जारी किया गया है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

यासकर, बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक-दो जाहां पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली और आंधी-बारिश को लेकर अलट है।

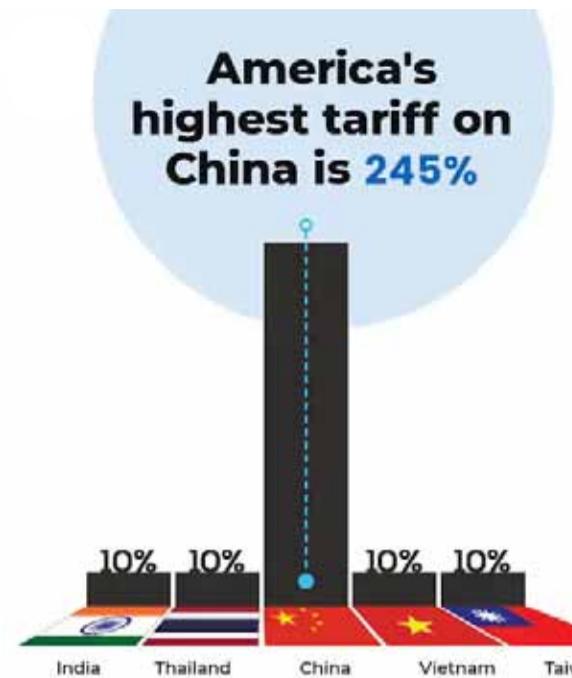
यासकर,

China now faces up to 245% tariff on imports: White House calls it result of retaliatory actions

Agency: The US announced that China now faces a new tariff of up to 245% due to its retaliatory measures, according to a statement by the White House on late Tuesday. The order also included explanations for the reciprocal tariffs announced on April 2. "China now faces up to a 245% tariff on imports to the United States as a result of its retaliatory actions," the White House said. "On Day One, President Trump initiated his America First Trade Policy to make America's economy great again," it said. "More than 75 countries have already reached out to discuss new trade deals. As a result, the individualised higher tariffs are currently paused amid these discussions, except for China, which retaliated," it added. Before the latest revision, a 145% tariff was being levied on Chinese exports to the United States. The US President Donald Trump had imposed reciprocal tariffs on dozens of countries with which

the US has a trade deficit. Later, President Trump had decided to pause the tariffs for 90 days after many countries initiated talks with the US administration for a trade deal.

Earlier, China had ordered the country's airlines to not to take any more deliveries of jets of the American airplane manufacturer Boeing, the international news agency, Bloomberg had said in a report. The agency had quoted sources as saying that the Chinese government had also ordered the domestic carriers to stop buying all aircraft-related equipment and parts from US companies. Before that, the Xi Jinping led government had also imposed restrictions on the export of seven rare earth materials which were used across crucial industries. Additionally, the world's second biggest economy had also halted shipments of magnets at Chinese ports that were essential for assembling everything from cars and drones to



robots and missiles. Earlier on April 14, 2025, the US President Trump had termed tariff exemptions on semiconductors as fake news.

And had said on social media platform, 'Truth Social' that he would put semiconductors and the 'WHOLE ELECTRONICS SUPPLY CHAIN' under

the National Security Tariff Investigations. The top Republican had added that the electronic items would be put under separate tariff bucket. The White House then stated that total additional tariffs on China imports actually stood at 245% due to all the retaliatory measures taken so far.

SC starts hearing on Waqf Amendment Act

Agency: The Supreme Court on Wednesday heard multiple petitions challenging the constitutional validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025.

It noted that undoing "waqf by user" would create several issues and sought the central government's reply to over 100 petitions challenging the Act. However, it refused to put a stay on the operation of the law. On inclusion of non-Muslim members in the Central and state Waqf boards, the apex court asked if the BJP-led Centre would "allow Muslims to be part of Hindu religious trusts". It ruled that ex-officio members could be appointed regardless of religion but others had to be Muslims. The top court noted that most of the mosques were built during 14th and 15th century and producing a "registered deed" was impossible. "Many of the masjids are created in 14th or 15th centuries. To require them to produce a registered deed is impossible. Most of the cases, say Jama Masjid Delhi, the waqf will be waqf-by-user," CJI Sanjiv Khanna said. "If you are going to de-notify

waqf-by-user properties, it will be an issue," he added. Kapil Sibal had argued that the abolition of the 'waqf by user' provision struck at the core of religious practice, asserting, "It's my integral part of religion, it's recognised in Ram Janmabhumi judgment.

Problem is, they will say if a waqf is created 3000 years ago, they will ask for deed."

The removal of the provision is another point of contention driving the anti-Waqf protests. Under the Waqf Act of 1954, properties could be designated as waqf if they had long been used for religious or charitable purposes, even in the absence of official documentation. The amendment does away with this classification, raising concerns and ambiguity over the legal status of many such properties. The apex court has sought clarification over non-Muslim members in the Waqf council. "Will you allow Muslims to be part of Hindu religious trusts," it asked. It said that ex-officio members could be appointed regardless of their faith but others members had



to be Muslims. According to the Act, in the Central Waqf Council, up to two of the 22 appointed (non-ex officio) members may be individuals from non-Muslim communities. State Waqf Boards may include up to two non-Muslim members among the 11 appointed (non-ex officio) positions. Addressing the anti-Waqf protests that turned violent in Bengal's Murshidabad killing three, SC said that it was "very disturbed". "Once Supreme Court is seized of the matter, this should not happen," the CJI said. Violent protests erupted in Murshidabad on April 11 over the contentious

in the Lok Sabha with 288 votes in favour and 232 against, while in the Rajya Sabha, it passed with 128 members supporting and 95 opposing it. However, a total of 72 petitions have been filed challenging the validity of the Act. Petitioners include AIMIM leader Asaduddin Owaisi, the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB), Jamiat Ulama-i-Hind, the DMK, and Congress MPs Imran Pratappgarhi and Mohammad Jawed. In response, the Centre filed a caveat in the Supreme Court on April 8, requesting to be heard before any orders are issued.

India first ATM on train launched on Mumbai Panchavati Express



plan. In order to accommodate the ATM, the coach was modified at the Manmad Railway Workshop. Railway authorities are now monitoring their performance closely so that network connectivity remains stable along the entire route, allowing passengers to withdraw cash without a problem. The Panchavati Express is a daily running train between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) in Mumbai and Manmad Junction in Nashik. Recognised for its timely schedule and quick journey duration, the total travel time covers around 4 hours and 35 minutes. In the event of a successful trial, more ATMs on other trains are likely to be installed by Indian Railways, making it convenient for travellers with the ability to withdraw money when on the run.

Justice BR Gavai likely to succeed Sanjiv Khanna as next Chief Justice of India

Agency: The name of Justice Bhushan R Gavai has been proposed as the next Chief Justice of India (CJI), with the Supreme Court forwarding the recommendation to the Law Ministry. The proposal came from the incumbent Chief Justice, Sanjiv Khanna, who is due to retire on May 13. As per convention, the sitting CJI recommends the senior-most judge in line as their successor. Earlier, the Law Ministry had formally requested Justice Khanna to name his successor, triggering the process of appointment. Justice Gavai, if appointed, will become the 52nd Chief Justice of India. He is likely to take the oath of the top judicial chair on May 14. However, Justice Gavai will serve as the Chief Justice of India only for six months as he is due to retire in November 2025. Justice Gavai was appointed as a judge of the Supreme Court

on May 24, 2019. Born on November 24, 1960, in Amravati, Maharashtra, he is the son of the late RS Gavai, a noted social activist and former Governor of Bihar and Kerala.

Justice Gavai began his judicial career as an Additional Judge of the Bombay High Court on November 14, 2003, and became a Permanent Judge on November 12, 2005. He served for over 15 years, presiding over benches at Mumbai, Nagpur, Aurangabad, and Panaji.

Notably, he will be the second Scheduled Caste judge to be appointed as Chief Justice of India, following the retirement of Justice KG Balakrishnan in 2010. Justice BR Gavai authored the majority opinion upholding the 2016 demonetisation scheme, affirming the Union government's power to declare currency invalid and stating that the scheme satisfied the 'test of proportionality'.

'Major terror plot foiled, infiltration route exposed,' say police

Agency: The four recent encounters in Jammu and Kashmir's Kathua district "exposed" the route used by terrorists to infiltrate into India from across the International Border (IB), a senior police officer said on Wednesday. Senior Superintendent of Police, Kathua, Shobhit Saxena also said the successful recovery of huge quantities of arms and ammunition, including explosives and daily-use items, was on display. He said a tight security grid was in place in the district, from the border villages to hinterland, leading to the successful operations against the terrorists. "The encounters exposed their traditional (infiltration) route... We will not allow them to use this route again," Saxena said. He said the recoveries showed that they had come with ill-intention and were prepared for a long stay. He said the seizure of a huge quantity of explosive material thwarted their plan to carry out Improvised Explosive Devices (IED) blasts, while some quantity of heroin suggested that they were also consuming drugs. He praised the



cooperation of the people in the anti-terrorist operations and said the "civil population helped us a lot and are providing immediate information which helped us in making an assessment about the terrorists on the run and we are accordingly planning our operations to neutralise them".

According to evidence, Saxena said terrorists had recently sneaked into this side from across the border but police "did not allow

Mamata Banerjee claims Bengal violence was planned

Agency: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said the violence over the Waqf law was "planned" and suggested a conspiracy by Union Home Minister Amit Shah and the BSF to allow the entry of Bangladeshi miscreants to fuel unrest in the state. In a meeting with Muslim clerics in Kolkata, the fiery Trinamool Congress chief assured them that her party was at the forefront in the fight against the Waqf law and urged them to engage in peaceful protests. "I urge the Prime Minister. He must rein in the Home Minister (Amit Shah). He is using all the agencies to plot against us. What will happen when Modi ji is not there?" Mamata said. This is not the first time that Mamata has trained her guns on Amit Shah while going soft on Prime Minister Narendra Modi. In 2022, Mamata said she didn't believe that the Prime Minister was behind the misuse of investigative agencies as CBI and ED were under the Home Ministry. Three people died and several were injured as Bengal's Murshidabad and South 24 Parganas districts witnessed widespread violence during protests over the passage of the Waqf law. Among the deceased are a father-son duo who were hacked to death by a mob in Samsherganj. The state government has announced Rs 10 lakh ex gratia for the families of the three persons who died in the violence. An initial probe into the riots



has revealed the involvement of Bangladeshi miscreants, according to a report sent to the Union Home Ministry. The districts where violence broke out border Bangladesh. Latching on to the charge, Mamata claimed that the BSF, which guards the 2,200 km Bangladesh border along Bengal, was responsible for letting miscreants in from the neighbouring country. "I saw a report that the Home Ministry said Bangladesh is involved in this (Murshidabad violence). If this is true, the Centre is responsible. BSF takes care of the border. Why did BSF not avert such a crisis?" the Chief Minister said. Calling the Waqf law BJP's "divide and rule policy", Mamata warned against the saffron party's polarisation tactics.

"If you have to protest, do it peacefully. The BJP will come and incite you, but imams must play a role and diffuse it, saying we won't allow division between Hindus and Muslims," she said. Mamata also rejected the BJP's claims that the Trinamool was involved in the Waqf violence. "Had the TMC been involved in Waqf violence as claimed by the opposition, the houses of its leaders would not have been attacked," the Trinamool chief said. While the Trinamool supremo held a meeting with Muslim clerics, the BJP observed Hindu Shaheed Diwas outside the state Assembly and paid tribute to those killed in the violence.

BJP HITS BACK

Union Minister and Bengal BJP chief Sukanta Majumdar took a swipe at Mamata Banerjee after she wrongly said that West Bengal shares a border with Sri Lanka, an island nation. "According to geography expert & Failed West Bengal CM Mamata Banerjee, the state now shares a border with Sri Lanka! Move over, maps — Didi's imagination has redrawn South Asia!" Majumdar said in a post on X. He didn't stop there. "When the Chief Minister herself can't tell where her state ends and an island nation begins, is it any wonder qualified teachers are jobless while scams thrive? In Mamata's Bengal, facts are optional, logic is missing, and incompetence is a qualification," Majumdar added.

ED questions Robert Vadra on day 2



was allowed to go home for lunch around 1.10 pm. Vadra was questioned for about five hours on Tuesday and his statement was recorded by the federal probe agency under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), official sources said. The 56-year-old Vadra had termed the ED action "political vendetta" saying the people of the country "do not trust the probe agencies". He said he has always cooperated with investigative agencies and has furnished huge amount of documents, stressing that there needs to be a closure in cases which are as old as 20 years. The probe against Vadra is linked to a land deal in Haryana's Manesar-Shikhpur (now sector 83) in Gurugram.